

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5092/2023

मनीषा अली पुत्री श्री मंजूर अली, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 4, मांडली रोड, सिमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.).

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव पंचायती राज के माध्यम से। राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डूंगरपुर (राज.).
3. सहायक प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिति, सिमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.).

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री के.के. शाह।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

23/02/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि प्रतिवादियों ने उसे कंप्यूटर शिक्षा में पीजी डिप्लोमा का प्रमाण पत्र देरी से जमा करने के कारण एलडीसी के रूप में नियुक्ति से इनकार कर दिया, जो कि पात्रता शर्तों में से एक है, जबकि उसके पास कट ऑफ तारीख से काफी पहले उक्त योग्यता थी।
2. पहले प्रासंगिक तथ्य। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में सीधी भर्ती के माध्यम से एलडीसी के पद के लिए आवेदन किया था। वह शुरू में सफल रही, लेकिन भर्ती प्रक्रिया विभिन्न

कारणों से 2022 तक रोक दी गई, जब सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषित की गई। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, ओबीसी श्रेणी के तहत याचिकाकर्ता को गुजरात से कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र को सत्यापन के बिना स्वीकार करने के संबंध में एक समस्या का सामना करना पड़ा। गुजरात में संस्थान से प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राप्त करने के लिए यानी राजस्थान राज्य के बाहर, कट ऑफ तारीख से परे देरी हो सकती थी। याचिकाकर्ता के पास गुजरात से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीजी डिप्लोमा (कट ऑफ डेट से पहले वर्ष 2012 में प्रदान किया गया) के अलावा राजस्थान स्टेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कट ऑफ डेट से बाद में वर्ष 2013 में प्रदान किया गया) का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी था। हालांकि, याचिकाकर्ता अनजाने में दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान गुजरात पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे उसकी उम्मीदवारी खारिज हो गई। उसने दावा किया कि एक अन्य उम्मीदवार को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने पर उसे स्वीकार कर लिया गया था। बाद में पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र जमा करने के बावजूद, चयन प्रक्रिया में अपने प्रदर्शन का लाभ प्राप्त करने के याचिकाकर्ता के प्रयास व्यर्थ रहे। इसलिए तत्काल याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिका के पैराग्राफ 5 में उल्लिखित विशिष्ट दावे ध्यान देने योग्य हैं। हालांकि, एक चूक के कारण, वह अपना 2012 का पीजी डिप्लोमा गुजरात प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रही। इस चूक के कारण उसकी उम्मीदवारी खारिज होने का हानिकारक परिणाम हुआ। अस्वीकृति नोटिस पंचायत समिति, सिमलवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया था। उसी दिन, सोनल भावसार नामक एक अन्य व्यक्ति का नाम अस्वीकार सूची में दिखाई दिया। उसे भी अपनी बी.एड मार्कशीट जमा नहीं करने के कारण शुरू में असफल माना गया था। हालांकि, बाद में जमा करने पर, उसके दस्तावेज़ स्वीकार कर लिए गए और उसे नियुक्त कर दिया गया। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने 10 अक्टूबर 2022 को प्रतिवादी संख्या-2 के डीलिंग क्लर्क को गुजरात राज्य का वर्ष 2012 का अपना पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र जमा किया, जिसने उसे आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ भी सकारात्मक सामने नहीं आया। 4. रिट याचिका पर दायर जवाब में याचिकाकर्ता के उपरोक्त दावे के संबंध में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 5. प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना आवश्यक है और यह मान लेना सुरक्षित होगा कि इसी तरह की स्थिति वाले अन्य उम्मीदवार को प्रमाण पत्र देर से जमा करने का लाभ दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता को इसी तरह के उपचार से वंचित किया गया है।

6. केवल समानता के आधार पर और यह भी देखते हुए कि याचिकाकर्ता के पास किसी भी मामले में कट-ऑफ तिथि से पहले गुजरात से अपेक्षित योग्यता है और यह केवल एक अतिरिक्त कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम था, जिसे उसने राजस्थान में अपने आत्म-सुधार के लिए किया था, जिसे कट-ऑफ तिथि के बाद बताया गया था। आधार में, यह ऐसा मामला नहीं है कि वह अपने अकेले लाभ के लिए कोई लाभ सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि को बदलने की मांग कर रही है।

7. गुजरात से उसके प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 के उसके पीजी डिप्लोमा का लाभ भी दिया जाए।

8. तदनुसार रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को तभी नियुक्त किया जाएगा, जब 2013 के विज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न नहीं) के अनुसार आज की तिथि तक एलडीसी के पद के लिए रिक्ति उपलब्ध हो, जिसके आधार पर उसके समकक्षों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया गया था।

9. यदि याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश की जाती है, तो वह 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी मौद्रिक लाभ की हकदार नहीं होगी, लेकिन उसे उसी तिथि से उसके प्रदर्शन के अनुसार वरिष्ठता सहित काल्पनिक लाभ दिए जाएंगे, जिस तिथि से अन्य लोगों की नियुक्ति हुई थी, जिन्होंने उसी चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।

10. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ संपर्क करने के चार सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक अभ्यास किया जाना चाहिए।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

रिपोर्टिंग के लिए फिट है या नहीं- हां/नहीं

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।